

FCI SIDBI ESIC BANK (**) (**)









IMPORTANT COMMITTES

2022

Full & Final

REVISION



BY PRIYA MAHENDRAS



UPCOMING ONLINE BATCHES







Q 1- The Animation, Visual Effects, Gaming and Comic (AVGC) Task Force set up by the Union Information and Broadcasting Ministry has submitted its report to the government, the committee will be headed by whom?

Q 1- केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक (AVGC) टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी?

- 1. Apurva Chandra
- 2. DY Chandrachood
- 3. Indra Nooyi
- 4. None of these



- Q 2- Who among the following constitutes a committee to conduct accessibility audit of Supreme Court premises for disabled?
- Q 2- निम्नलिखित में से कौन विकलांगों के लिए सुप्रीम कोर्ट परिसर की सुगम्यता लेखापरीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन करता है?

- 1. DY Chandrachud
- 2. S Ravindra Bhat
- 3. Dr Sanjay Jain
- 4. V Sridhar Reddy



Q 3- Which state government has constituted a task force to recommend regulation of online gambling and gaming?

Q 3- किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुए और गेमिंग के नियमन की सिफारिश करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है?

- 1. Uttar Pradesh
- 2. Madhya Pradesh
- 3. Kerala
- 4. Maharashtra



This task force will be headed by the state chief secretary Iqbal Singh Bains.

इस टास्क फोर्स का नेतृत्व राज्य के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस करेंगे।

The task force has been constituted to examine various judicial precedents, legal situations, and technical aspects related to prevention and control online gambling and gaming and make recommendations to the state government.

टास्क फोर्स का गठन विभिन्न न्यायिक मिसालों, कानूनी स्थितियों और ऑनलाइन जुआ और गेमिंग की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित तकनीकी पहलुओं की जांच करने और राज्य सरकार को सिफारिशें करने के लिए किया गया



Q 4- Who among the following has approved the formation of an Advisory Group for streamlining the development of the Bamboo sector?

Q 4- निम्नलिखित में से किसने बांस क्षेत्र के विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए एक सलाहकार समूह के गठन को मंजूरी दी है?

- 1. Narendra Modi
- 2. Dharmendra Pradhan
- 3. Narendra Singh Tomar
- 4. Amit Shah



National Bamboo Mission

- It was launched during 2018-19 as a Centrally Sponsored Scheme.
- इसे 2018-19 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था।
- It is being implemented as a sub-scheme of Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH).
- इसे एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) की एक उप-योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।
- The Department of Agriculture and Cooperation (DAC) of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare is the nodal agency for its implementation.
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का कृषि और सहकारिता विभाग (DAC) इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।



Q 5- Government of India has set up a panel to set a timeline for adoption of common standard charger in India, the committee will be headed by whom?

Q 5- भारत सरकार ने भारत में सामान्य मानक चार्जर को अपनाने के लिए एक समयरेखा निर्धारित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है, समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी?

- 1. Nidhi Khare
- 2. Madhabi Puri Buch
- 3. Nirmala Sitharaman
- 4. None of these



The Department of Consumer Affairs under the Union Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution has formed a committee to set a timeline for the adoption of USB Type-C as the standard charging port for electronic products, including smartphones, tablets and laptops.

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग ने स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप सहित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए यूएसबी टाइप-सी को मानक चार्जिंग पोर्ट के रूप में अपनाने के लिए एक समयरेखा निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया है।



Q 6- The government has constituted a committee to review the gas pricing formula for gas produced in the country with the aim to ensure a fair price, the committee will be headed by whom?

Q 6- सरकार ने उचित मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश में उत्पादित गैस के गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है, समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी?

- 1. Kirit Parikh
- 2. Nidhi Khare
- 3. Madhabi Puri Buch
- 4. Nirmala Sitharaman



Q 7- The Capital market regulator Securities Exchange Board of India (SEBI) has formed a 20 member high level panel to review the extant corporate takeover rules, it will be lead by whom?

Q 7- पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मौजूदा कॉर्पोरेट अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए 20 सदस्यीय उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा?

- 1. Justice Satish Chandra Sharma
- 2. Justice Shiavax Jal Vazifadar
- 3. Justice Rajesh Bindal
- 4. Justice Pankaj Mithal



The Capital market regulator Securities Exchange Board of India (SEBI) has formed a 20 member high level panel to review the extant corporate takeover rules.

पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मौजूदा कॉर्पोरेट अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए 20 सदस्यीय उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है। The 20 member panel will be headed by the former chief justice of Punjab and Haryana High Court Justice Shiavax Jal Vazifadar. 20 सदस्यीय पैनल की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश शियावक्स जल वज़ीफ़ादार करेंगे।

The takeover code was last reviewed in 2009 by the Achutan committee. अधिग्रहण संहिता की आखिरी समीक्षा 2009 में अच्युतन समिति द्वारा की गई थी।



Q 8- The central government has constituted a committee to improve the MNREGA scheme. The first meeting of this committee was headed by_____?

Q 8- केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति की पहली बैठक _____ की अध्यक्षता में हुई थी?

- 1. Rituraj Awasthi
- 2. Giriraj Singh
- 3. BS Chauhan
- 4. Amarjit Sinha



The central government has constituted a committee to improve the MNREGA scheme. This committee will examine the efficacy of MGNREGA as a means of poverty alleviation. केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति गरीबी उन्मूलन के साधन के रूप में मनरेगा की प्रभावशीलता की जांच करेगी।

The first meeting of this committee, headed by former Rural Development Secretary Amarjit Sinha.

इस समिति की पहली बैठक पूर्व ग्रामीण विकास सचिव अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में हुई.



Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) scheme

- MNREGA Act was passed by the Indian Parliament on 23rd August 2005 but it came into force on February 6, 2006.
- मनरेगा अधिनियम 23 अगस्त 2005 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन यह 6 फरवरी, 2006 को लागू हुआ।
- On 2nd October 2009 an amendment was made in the National Rural Employment Guarantee Act 2005, to change the nomenclature of the Act from NREGA to MGNREGA.
- 2 अक्टूबर 2009 को अधिनियम के नामकरण को नरेगा से मनरेगा में बदलने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया।



- The mandate of the MGNREGA is to provide at least 100 days of guaranteed wage employment in a financial year to every rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work.
- मनरेगा का जनादेश प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं।
- The scheme is under the administrative control of the Union Ministry of Rural Development.
- यह योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।



Q 9- Who among the following has been appointed as the chairperson of the 22nd Law Commission?

Q 9- निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?

- 1. Justice Ravi R. Tripathi
- 2. Justice S.Siva Kumar
- 3. Justice B S Chauhan
- 4. Justice Ritu Raj Awasthi



The Union ministry of Law and Justice constituted the 22nd Law Commission on 7 November 2022 and appointed former Karnataka High court chief justice Rituraj Awasthi as the chairperson of the Law Commission.

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 7 नवंबर 2022 को 22वें विधि आयोग का गठन किया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया।

The five member 22nd Law Commission will have a term of three years. पांच सदस्यीय 22वें विधि आयोग का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

Justice BS Chauhan was the chairman of the 21st Law Commission whose term expired in August 2018.

न्यायमूर्ति बीएस चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त हो गया था।



Q 10- Which ministry has set up a high level committee for strengthening the Assessment & Accreditation of Higher Educational Institutions?

Q 10- उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन को मजबूत करने के लिए किस मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है?

- 1. Ministry of Education
- 2. Ministry of external affairs
- 3. Ministry of Commerce
- 4. Ministry of Housing and Urban Affairs



The Government of India has set up a four member high level committee for strengthening the Assessment & Accreditation of Higher Educational Institutions under the chairmanship of Dr. K. Radhakrishnan. भारत सरकार ने डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन को सुदृढ़ करने के लिए चार सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।



Q 11- Which committee has been constituted by govt to examine the existing framework with regard to virtual currencies?

Q 11- आभासी मुद्राओं के संबंध में मौजूदा ढांचे की जांच के लिए सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है?

- 1. H R Khan committee
- 2. Dinesh Sharma Committee
- 3. Shaktikant committee
- 4. B S Dhamaraj committee



Q 12- National Education Policy, 2020 is based on the recommendation of which of the following committee?

Q 12- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर आधारित है?

- 1. Nagarajan committee
- 2. Goswami committee
- 3. Kasturirangan committee
- 4. Pranav Ray Committee



Q 13- Which committee was appointed to look into forming of Telangana as a new state?

Q 13- तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी?

- 1. Chidambaram committee
- 2. Srikrishna committee
- 3. Duggal committee
- 4. None of the above



- This committee was headed by Justice B. N. Srikrishna.
- Telangana was formed on 2 June 2014.
- इस समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण थे।
- तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था।



- Q 14- Which committee was set up to review the concept of Poverty line?
- Q 14- गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था?

- 1. Suresh Tendulkar Committee
- 2. Lakdawala committee
- 3. Wanchoo committee
- 4. Dutt committee



- Lakdawala committee –estimating poverty line (1993)
- Wanchoo committee —industrial development for the backward areas
- **Dutt committee** working of the licencing system
- लकड़ावाला समिति गरीबी रेखा का आकलन (1993)
- वांचू समिति पिछड़े क्षेत्रों के लिए औद्योगिक विकास
- दत्त समिति लाइसेंस प्रणाली की कार्यप्रणाली



Q 15- Which committee has given the recommendation to reduce the burden of school bags?

Q 15- स्कूल बैग का बोझ कम करने की सिफारिश किस समिति ने दी है ?

- 1. Yashpal committee
- 2. National Commission for women
- 3. Ramamurti committee
- 4. National education policy 1986



Q 16- India's first National Policy on Education was a sequel to the recommendation of which of the following committee?

Q 16- शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश की अगली कड़ी थी?

- 1. Kothari commission
- 2. Mudliyar Commision
- 3. Ramamurti Review committee
- 4. Radhakrishnan Committee



National Education Commission popularly known as Kothari commission.

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है।

Formed on 14 July 1964 under the chairmanship of Daulat Singh Kothari.

14 जुलाई 1964 को दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित।

Q 17- Kelkar committee is related with ____?

Q 17- केलकर समिति से संबंधित है?

- 1. Industrial pollution
- 2. Tax reforms
- 3. Babri masjid issue
- 4. Railway accidents



Q 18- Which committee was formed to evaluate and study PPP (Public-private-Partnership)?

Q 18- पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरिशप) के मूल्यांकन और अध्ययन के लिए किस समिति का

गठन किया गया था?

- 1. Desai committee
- 2. Lakdawala committee
- 3. Kelkar committee
- 4. Tendulkar committee



Q 19- Which committee has recommended change in the structure and ecosystem in the Indian Cricket Board?

Q19 - किस समिति ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड में संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव की सिफारिश की है?

- 1. Lodha committee
- 2. Gavaskar committee
- 3. Mehta committee
- 4. Guha committee



Q 20- Central vigilance commission was set up on the recommendation of which committee?

Q 20- केंद्रीय निगरानी आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी?

- 1. Gorewala committee
- 2. Nachiket Mor committee
- 3. Usha Thorat Committee
- 4. Santhanam committee



